संकल्प, 1956 में दिये गए सिद्धान्तों के अनुसार सरकारी क्षेत्र की प्रयोजनाओं की स्थापना की जाती है।

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र में लगाई गई पूंजी की तुलना सरकारी क्षेत्र में लगायी गयी पूंजी से नहीं की जा सकती, तथा दोनों क्षेत्रों की आमदनियां की वास्तविक तुलना करना व्यवहार्य नहीं है। किसी भी हालत में, उद्यमों द्वारा दिया जाने वाला कर ही सम्बद्ध उद्यम की कुशलता का मानदण्ड नहीं है।

(ग) सबसे हाल के जिस वित्तीय वर्ष के लेखे उपलब्ध हैं उसके, अर्थात् 1968 के 31 मार्च को केन्द्रीय सरकार के 83 औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रम थे। इन उद्यमों में कुल 3333 करोड़ रुपये की रकम लगी हुई थी, जिसमें से 3029 करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार ने दिया था तथा बाकी रकम राज्य सरकारों, भारतीय गैर-सरकारी पार्टियों तथा विदेशी पार्टियों ने दी थी।

जहां तक आमदनी का सम्बन्ध है, 1967-68 में, निर्माणाधीन उपक्रमों तथा भारतीय जीवन बीमा निगम को भी छोड़कर, सरकारी उद्यमों को कुल 35 करोड़ रुपये की वास्तविक हानि हुई थी। लेकिन, यह हानि मूल्य ह्रास के लिए 121 करोड़ रुपये, व्याज के लिए 74 करोड़ रुपये तथा कर के लिए 19 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने के बाद हुई। इन रकमों को हिसाब में लेने के बाद, वर्ष में किये गए काम के परिणाम के रूप में कुल 179 करोड़ रुपये का अधिशेष निकलता है। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र में उद्यमों ने इसी वर्ष 175 करोड़ रुपये का उत्पादन-शुल्क राजकोष को दिया है।

जीवन बीमा निगम के मामले में, सबसे हाल के, अर्थात् 1 अप्रैल, 1965 से 31 मार्च, 1967 की दो वर्षों की अवधि के मूल्यांकन के अनुसार, अधिशेष की रकम 72·28 करोड़ रुपया थी जिसमें से 68.67 करोड़ रुपया पालिसी होल्डरों के लिए तथा 3·61 करोड़ रुपया सरकार के लिए निर्धारित किया गया।

Availability of Life Saving Drugs

*927. DR. M. SANTOSHAM : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether the need for flying-in life saving drugs for the treatment of late C.N. Annadurai was due to stocks exhausted in this country or through a ban on import of these drugs ; and

(b) whether Government propose to ensure that these drugs hereafter are available for all citizens ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI K. K. SHAH) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha in due course.

Allotment of Restaurant in Mohan Singh Market, New Delhi to Emergency Commissioned Officers.

*928. DR. KARNI SINGH :
SHRI M. L. SONDHI :

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Government have issued any instructions to the State Governments and Union Territories that, all things being equal, the released Emergency Commissioned Officers be given special consideration to rehabilitate themselves ;

(b) whether Government's attention has been drawn that the tender of the released Emergency Commissioned Officers for the allotment of a restaurant in Mohan Singh Market was turned down by the New Delhi Municipality though it was the highest ; and